

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 117 / 2017 राजस्व अपील

1. बाबूलाल पुत्र मुरलीनाथ जाति जोगी निवासी गुजर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा ।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश योग्य अधिनस्थ नायब तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा
दिनांक 10.11.2017 प्रकरण संख्या 26/2017 अ.धारा 91 रा.भू.रा. अधि. अ. धारा 75
राज.भू.रा. अधिनियम

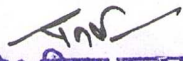
उपस्थिति : श्री बृजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलान्त उप0 ।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

:— निर्णय :—

दिनांक: 27.11.2017



संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मीणा सीमला तहसील सिकराय में ओमप्रकाश चौधरी ने आबादी भूमि से 439 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत मीणा सीमला पंचायत समिति सिकराय से दिनांक 05.10.04 को 6585/- रूपये नजराना भुगतान कर प्राप्त किया था। पट्टाधारी ओमप्रकाश एवं बाबूलाल ने पट्टा शुदा भूमि को दिनांक 14.06.16 को श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि बाबूलाल को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र बेचना कर दिया व पट्टा शुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाया हुआ है। पट्टा शुदा भूमि पर श्री श्री ओमदास आश्रम बना हुआ है, जिसमें यात्री निवास करते हैं। पट्टा गृहितागण के नाम ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित पट्टा का असमलेख ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति सुमन मीणा के पास से चोरी हो गया, जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 87/2012 पुलिस थाना महन्दीपुर में दिनांक 28.06.12 को उपस्थित किया गया जिस पर अन्तिम प्रतिवेदन लगाया गया दिनांक 22.08.12 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय द्वारा एफ.आर स्वीकार हुई। तहसीलदार सिकराय ने क्वेटी श्रीमति लक्ष्मीदेवी द्वारा आश्रम के निर्माण के दौरान वर्तमान भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 193/2 में से 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपीलान्त के नाम सूचना पत्र प्रेषित किया और खसरा नं. 193/2



अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

को चारागाह भूमि बताया गया। अपीलान्त ने अपना उत्तर अन्तर्गत धारा 91(6) रा.भू.रा. अधिनियम का तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसपर पटवारी के प्रतिवेदन के बाद दिनांक 17.02.16 को निरस्मत फरमाया गया। पटवारी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं होना बताकर प्रतिवेदन पेश किया गया। ग्राम मीणा सीमला में बाद भू-प्रबन्ध चारागाह भूमि व आबादी भूमि के खसरा नं. परिवर्तित हुए तथा चारागाह भूमि में खसरा नं. 275 एवं आबादी भूमि के खसरा नं. 260 बनाये गये। आश्रम निर्माण हो जाने के डेढ वर्ष बाद पटवारी हल्का ने दिनांक 18.10.17 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के समक्ष संवत् 2074 में खसरा नं. 275 रकबा 1.15 है० भूमि के 1 एयर भू-भाग पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा (गेस्ट हाउस) का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्त को दिनांक 03.11.17 को तलब किया। अपीलान्त ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत कर निर्माण पट्टा शुदा भूमि पर होने का निवेदन किया और कार्यवाही ड्राप करने की प्रार्थना की किन्तु तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.11.17 को प्रश्नगत आदेश अपीलान्त को बेदखल करने व 12 रुपये शास्ति जमा कराने के आदेश फरमाये है। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।



अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने गेस्ट हाउस निर्माण कर अतिक्रमण करने के लिए अपीलान्त के विरुद्ध सूचना पत्र जारी किया है जबकी गेस्ट हाउस अपीलान्त का नहीं है। अपीलान्त की पत्नि श्रीमति लक्ष्मी देवी की सम्पत्ति है जो आबादी भूमि पट्टा शुदा में बना हुआ है। गेस्ट हाउस सन् 2004 से बना हुआ है। सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तहसीलदार द्वारा गेस्ट हाउस को आबादी भूमि पर नहीं मानकर राजकीय भूमि पर माना है। 1 एयर भूमि का क्षेत्रफल 100 मीटर बनता है। आबादी भूमि पर पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 439 वर्गगज का दिनांक 05.10.04 को प्रचलित किया गया है। उक्त भूमि को लक्ष्मी देवी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.03.16 को कय किया है। प्रश्नगत आदेश मौके की स्थिति के विपरित फरमाये जाने के कारण खण्डनीय है। गेस्ट हाउस 100 वर्गमीटर पर नहीं बल्कि 367.57 वर्गमीटर पर बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा आराजी खसरा नं. 275 वाके ग्राम मीणा सीमला के भू-प्रबन्ध से पूर्व खसरा नं. 193/2 के 1 बिस्वा पर अपीलान्त का अतिक्रमण बताकर दिनांक 23.09.13 को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया पुनः


अति० जिला कलेक्टर
दौसा

26.09.13 को प्रकरण सं. 777 / 13 में नोटिस अन्तर्गत धारा 91(6) जारी किया गया जो दिनांक 17.02.16 को निरस्त कर कार्यवाही ड्राप की गई। दिनांक 17.02.16 के आदेश के बाद दिनांक 10.11.17 का आदेश अपीलान्त को परेशान कर अनुचित रूप से लाभ उठाने का प्रयास है। खसरा नं. 275 चरागाह व खसरा नं. 260 आबादी भूमि पास पास है। आबादी भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत को प्राप्त है। सीमाज्ञान के समय ग्राम पंचायत के सरपंच या पट्टा शुदा भूमि के मालिका को कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया। प्रश्नगत आदेश माप के आधार पर है तो गेस्ट हाउस का कौनसा भाग अतिक्रमित है वर्णित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाकर

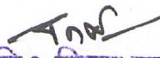


अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मीणा सीमला तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि खसरा नं. 275 कुल रकबा 1.15 है 0 किस्म गैर मुमकिन विश्रान्तिगृह मे से 0.01 है 0 पर गेस्ट हाउस बनाकर कब्जा करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना शास्ति राशि आरोपित करने के आदेश दिनांक 10.11.17 को पारित किये गये है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गेस्ट हाउस के वास्तविक मालिक श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि बाबूलाल जोगी को अतिक्रमण बाबत नोटिस नहीं दिया गया है तथा अतिक्रमण किस भाग पर किया गया है। यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर अपीलान्त की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर एवं अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि


अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 117 / 2017 राजस्व अपील

प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दौसा